

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (जी आई० के० गुजराल) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) भूमि के आवंटन के लिए सरकारी नीति की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताये हैं :—

- (i) आवंटन ऐसे संस्थानों को किया जाता है जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत हैं और जिनका स्वरूप लाभ उठाना नहीं है।
  - (ii) आवंटन पूर्व निर्धारित दरों पर किया जाता है।
  - (iii) आवंटनी-संस्थान के लिए उम तारीख के दो वर्षों की अवधि के भीतर अपने भवन का निर्माण पूरा करना अपेक्षित है जिस तारीख को संस्थान की भूमि दे दी गई, और
  - (iv) आवंटनी-संस्थान के भंग हो जाने की स्थिति में भूमि उन्नी प्रकार के लक्ष्य और उद्देश्यों वाली एक पंजीकृत संस्था को हस्तान्तरित की जानी है और ऐसा न हो पाये तो यह सरकार को वापिस मिल जाती है।
- (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

#### पक्षियों की किस्मों की समाप्ति

6919. श्री मूलचन्द्र ढागा : क्या कुचि मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अप्रैल, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के 'भारतीय पक्षियों की तीन किस्मों की समाप्ति, बहुत-सी किस्में समाप्ति की ओर' (श्री इण्डियन बर्ड स्पेशीज एक्सपर्ट, मैनी आन के) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर विलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कुचि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) जी हां। दिनांक 26 अप्रैल, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित रिपोर्ट, संरक्षण विषयक कार्यकारी दल द्वारा वातावरण सम्बन्धी योजना और समन्वय विषयक राष्ट्रीय समिति को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर आधारित थी।

(ख) लुप्तप्राय नसले पहले ही संरक्षित घोषित कर दी गई है। उनके निर्यात पर रोक लगा दी गई है। चिडियाघर में लुप्तप्राय पक्षियों के प्रजनन को संरक्षण के अन्तर्गत, आरम्भ करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। वन्य प्राणी संरक्षण के लिए कानून को कड़ा करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

#### Eradication of Unemployment in Rural Areas of Tripura

6920. SHRI DASARATHA DEB : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the scheme to eradicate rural unemployment has started functioning in the State of Tripura ; and

(b) if so, the number of persons provided employment in each Block, particularly in the Development Blocks in the State ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The number of persons employed and the duration of their employment vary from scheme to scheme. Data of employment generated are collected in terms of mandays. The total number of mandays of employment created upto the end of February 1972, as reported by the State Government of Tripura, is 91,130. Since the district is taken for the appropriate unit for the allotment of funds the Crash Scheme for Rural Employment no date of generation of employment for the individual blocks are collected.